



2026:AHC:66428

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 4663 वर्ष 2026

राजन रोहतगी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अकलंक कुमार जैन

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: संजय अग्रवाल, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 74

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना; प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता; राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता के रूप में भी अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत संख्या-319 वर्ष 2025 (रुचि बनाम श्री राजन रोहतगी) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या-2, रामपुर द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 26.11.2025 को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत ये कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण है। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने प्रतिपक्षी संख्या-2 को वाहक चेक दिया था। प्रतिपक्षी संख्या-2 ने आवेदक की उपस्थिति में चेक के पीछे हस्ताक्षर किए और आवेदक द्वारा प्रतिपक्षी संख्या-2 के हस्ताक्षर को सत्यापित किया गया है। जब प्रतिपक्षी संख्या-2 ने बैंक के समक्ष चेक जमा किया, तो उसे गैर-सीटीएस चेक के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में आरोप लगाया गया आरोप झूठा, निराधार है और वैवाहिक विवाद के संबंध में पक्षगण के बीच कई विवाद लंबित हैं। प्रतिपक्षी संख्या-2 को चेक जारी करने का कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवसर नहीं है और वर्तमान चेक बैंक द्वारा 'नॉन सीटीएस चेक' टिप्पणी के साथ वापस कर दिया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत वर्तमान शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश मनमाना और अस्थिर है और इसे रद्द किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन तथ्यों और अन्य भौतिक सबूतों की चर्चा के बिना है। अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1383 में रिपोर्ट किए गए लल्लन कुमार सिंह और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उक्त निर्णय के प्रस्तर-38 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"38. प्रक्रिया जारी करने का आदेश एक खाली औपचारिकता नहीं है। मजिस्ट्रेट को अपने दिमाग को लागू करने की आवश्यकता है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। इस तरह की राय के गठन को आदेश में ही बताया जाना आवश्यक है। आदेश को रद्द करने योग्य है यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान कोई कारण नहीं दिया जाता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश में विस्तृत कारणों की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 191 कॉम्प कैस 177 (एस.सी.) के मामले में इस अदालत के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है; (2015) 4 एस.सी.सी. 609, जो इस प्रकार पढ़ता है:

"51. दूसरी ओर, संहिता की धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे से संबंधित है, यदि मजिस्ट्रेट की राय में किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। यह धारा एक आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। यदि मजिस्ट्रेट किसी मामले का संज्ञान लेता है (यह शिकायत प्राप्त करने वाला मजिस्ट्रेट हो सकता है या जिसे इसे धारा 192 के तहत स्थानांतरित किया गया है), तो उसके समक्ष सामग्री (यानी, शिकायत, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच, यदि मौजूद है, या जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो) पर



विचार करने पर, तो वह सोचता है कि किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला है, तो वह आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करेगा।

प्रक्रिया को देने या अस्वीकार करने के बारे में एक व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है और इसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति को केवल इसलिए अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए क्योंकि शिकायत दर्ज की गई है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बन गया है, तो मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए और इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सोचता है कि इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है।

हालांकि, धारा 204 में दिखाई देने वाले शब्द 'कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार' बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह वे शब्द हैं जो पर्याप्त रूप से सुझाव देते हैं कि एक राय केवल दिमाग के अनुप्रयोग के बाद ही बनाई जानी चाहिए कि उक्त आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और इस तरह की राय का गठन आदेश में ही कहा जाना है। आदेश को रद्द किया जा सकता है यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान कोई कारण नहीं दिया जाता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, हालांकि आदेश में विस्तृत कारणों की आवश्यकता नहीं है। एक *fortiori*, आदेश कानून में बुरा होगा यदि दिया गया कारण गलत साबित होता है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-2 के अधिवक्ता ने उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता या दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।

5. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर विचार किया और अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अधिवक्ता की प्रस्तुति कि शिकायत में दायित्व के कारण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है जिसके द्वारा आवेदक ने चेक दिया था। शिकायत की सामग्री के प्रस्तर-1 में, यह कहा गया है कि आवेदक ने उधार ली गई राशि का भुगतान करने के लिए, आंशिक भुगतान के रूप में वर्तमान विवादित चेक जारी किया और चेक बाउंस हो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है जिसमें आवेदक के हस्ताक्षर शामिल हैं। इस संबंध में आवेदक की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिकायत के प्रस्तर-1 में, प्रतिपक्षी संख्या-2 के पक्ष में चेक जारी करने का कारण बताया गया है कि आवेदक और प्रतिपक्षी संख्या-2 के बीच कुछ देयता के लिए, प्रतिपक्षी संख्या-2 के पक्ष में चेक जारी किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि आवेदक ने एक चेक जारी किया है और आवेदक के हस्ताक्षर चेक और इस संबंध में प्रस्तुत किए गए थे कि चेक जारी करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि पक्षों के बीच कई विवाद लंबित हैं, इस तर्क की जांच नहीं की जा सकती है।

6. विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 26.11.2025 के आदेश के संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि यह लल्लन कुमार सिंह और अन्य (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए अनामत आदेश है, समन आदेश के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों पर विचार किया है कि 27.04.2025 को आवेदक ने चेक दिया था और उसे बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसका अनादर किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने शिकायत की सामग्री, शिकायतकर्ता के बयान, चेक, पंजीकृत नोटिस और अन्य भौतिक साक्ष्यों पर भी विचार किया है और आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाया है और समन जारी किया है। समन आदेश के अवलोकन पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना आदेश पारित किया गया है और आक्षेपित आदेश गैर-बोलने वाला आदेश है। आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित है और आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता और दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सबमिशन की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है।

7. श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल और 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2897 में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य में, इस न्यायालय ने माना कि एक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है, जब तक कि तत्सम्य विपरीत साबित न हो जाए और इसलिए, उच्च



न्यायालय कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में अभियुक्त की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने और शिकायत को रद्द करने में उचित नहीं था।

15. इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह माना गया था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि इस तरह की धारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को मुकदमे में अपना बचाव करना चाहिए।

16. राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में जाकर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में एक वैधानिक अनुमान लगाती है।

17. रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (दिल्ली का एन.सी.टी.) में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कोई कानूनी धारणा होती है, तो शिकायत को रद्द करने के लिए पूर्व-परीक्षण चरण में तथ्य के विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"17. जैसा कि ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अदालत को पूर्व-परीक्षण चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सबूत को जोड़ने के बिना तथ्यात्मक बचाव को एक अभेद्य गुणवत्ता की आवश्यकता है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।

18. पूर्व-परीक्षण चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के



परिणामस्वरूप पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से बाहर कर दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी अनुमान के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा।

19. इस प्रकार, शिकायतकर्ता पर मुकदमा न करने के लिए, सम्मन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को अभी तक प्रचारित नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, तो हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन यहां आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाही प्रारंभिक चरण में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने के योग्य नहीं है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय, प्रस्तर-13 और 18 में कहा है कि:

"13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में, यह परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े कि क्या चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद अनुचित थी क्योंकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत, एक धारणा है कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ था। इस अनुमान का खंडन मुकदमे में किए गए सबूतों द्वारा किया जा सकता है। एक फोर्टियोरी, उक्त मुद्दे को उचित



रूप से या तो मुकदमे में, या बाद में, मुकदमे के समापन पर, अपील/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

"18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में, पूर्व-परीक्षण चरण में एक रोविंग जांच करके एक त्रुटि की है। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के योग्य नहीं थी, खासकर जब शिकायत के आरोपों से पता चला कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के आवश्यक अवयवों की पूर्ति प्रथम दृष्टया शिकायत के आरोपों से बनाई गई है, इसलिए हमारे विचार में, न तो समन आदेश और न ही शिकायत को उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण चरण में रद्द किया जा सकता था।

9. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

मीनू सिंह

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)